

RAJYA SABHA

Friday, the 7th August, 1992/the 16th Sravana, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the clock. The Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Survey on the problems of street Children

*441. DR. BAPU KALDATE: +

SHRI MENTAY PADMANABHAM:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitems which appeared in the Economic Times of 17th July, 1992 regarding survey conducted on the street children in the metropolitan cities of the country;

(b) whether Government propose to conduct a survey to children in the metropolitan cities; and

(c) if so, what steps are contemplated by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI K. KAMALA KUMARI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Government of India has with UNICEF assistance, already conducted six survey-studies of Street Children of Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad and Madras to understand the relevant facts and problems concerning street children. Three of the studies have already been publicised while the remaining three are under publication. The news-item appearing in the Economic Times of 17th July, 1992 is the fact based on the Government of India-UNCEF Survey.

+The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

डा. बपू कालदाते: : उपसभाध्यक्ष महोदया, एक सो प्रनुवाद के प्रति मेरा व्याप्तिपूर्ण है क्योंकि यह जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, ये भवारा ही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि इसका जो हिन्दी प्रनुवाद हो गया है वह है आवारा-बेसहारा। आवारा इज ए बेगाबोड़। लेकिन जो बच्चे आजकल रास्तों पर हैं ये सभी कोई आवारा बच्चे नहीं हैं। इसलिए पहले सो मुझे प्रनुवाद से आप्तिपूर्ण है, उसको दुरुस्त करता चाहिए क्योंकि यह एक गलत इन्प्रेशन दे रहा है, बच्चों के बारे में गलत इन्प्रेशन देता है।

अब मेरा सवाल यह है महोदया, कि आप जानती हैं कि दिखता अधिकेपूर्ण नागरीकरण और हर रोज बढ़ती हुई आवादी के कारण है यह और कारण है कि लाखों बच्चे, खासकर गरीबों, निम्न जाति के लाखों बच्चे रास्ते पर आ रहे हैं और वे खासकर शहरों में जाते हैं। क्योंकि देहतों में उनके लिए कोई काम नहीं होता है। महोदया, मैं इस प्रश्न को गंभीरता से इस कारण ले रहा हूँ कि मैं भानता आया हूँ कि घनांघता और दिर्द्रिता दोनों असामाजिकता के बुनियादी कारण हैं। जो घनांघता है, उनको असामाजिकता हम लोग देख रहे हैं रोज अव्वारों में पढ़ते हैं और वह दरिद्र लोग हैं इनको असामाजिकता का शिकार बानया जाता है, डेलीकंट खाया जाता है, वे होता नहीं जाते। आप देखते हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं, जो कूड़ीदान में कुत्तों के साथ खाना खाते हैं। हम देखते हैं ये जो गरीबों के बच्चे हैं ये नशीले पदार्थों का लेन-देन करते वालों के शिकार बन जाते हैं। आप मुख्यई चले जाइए, आप जानती होंगी कि मुख्यई में भिखारी बनने की शिक्षा देने का स्कूल है। अधिकृत संस्थान नहीं है लेकिन वहां शिक्षा देने की व्यवस्था है। शायद अर्जुनसिंह जी, उन संस्थान को एक बार देख ले कि वहां कैसे व्यवस्था चलती है। उनके हाथ छोटे किए जाते हैं ...

उपसभापति: आप संक्षेप में प्लीज बोल दीजिए। इससे कुछ ज्यादा सोग बोल सकेंगे।

डा. बापू कालदाते : दिल्कुल, बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया ।

मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि
यह जो बहुत बड़ी असामाजिकता दरिद्रता
के कारण उपज रही है, आप कह रहे हैं
कि आपने 6 अध्ययन किए हैं। लेकिन
सरकार का काम सिर्फ़ सर्वे या अध्ययन
करना ही नहीं होता। सरकार का काम
है उनसे जो तथ्य सामने आये हैं, उन
सभ्यों के प्रति आप क्या कर रहे हैं।
तो मेरा पहला सवाल सिर्फ़ यह है कि
जो सर्वेक्षण आपने किया है, जो अध्ययन आपने
किया है उसके नतीजे क्या आए हैं और
उस अध्ययन के नतीजों के अनुसार सरकार
उनके कार्यान्वयन की दिशा में कौन से
कदम उठाना चाहती है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम के परी) :
उपसभापति महोदया, प्रश्नकर्ता के प्रति
आभार प्रकट करता हूँ, इसलिए कि ये
हमारे देश को धरोहर ही नहीं, इन पर
भारत का भविष्य भी निर्भर करता है। यह
भी सत्य है कि सम्पन्न परिवारों के बच्चे
और दिल्लि बच्चे दोनों के अंदर, एक
सम्पन्नता में दुर्गुण है और एक विपन्नता
में दुर्गुण है, मगर विपन्नता है ।

प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि
इनके समाधान के लिए कौन सी योजना
है, क्या तरीका है, सर्वप्रथम में उनकी
सूचना के लिए यह कहना चाहता हूँ कि
इनके प्रति सरकार सचेत जरूर है,
मगर योजना में जो धन की आवश्यकता
होती है, वह भी उपयुक्त नहीं है।
योजना के अंतर्गत बच्चों को सुधारने के
लिए ओब्जर्वेशन होम्स हैं, स्पेशल
होम्स हैं और आफ्टर केयर
होम्स भी हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि
प्रश्नकर्ता ने आपने प्रारंभिक शब्दों में
आवारा शब्द पर एतराज किया, यह सत्य
है कि यह बसहारा, निराश्रित है, यह तो
साहित्यिक विश्लेषण का प्रश्न है
(व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : साहित्यिक
प्रश्न पूछने का हक तो मुझ को है ।

श्री सीताराम के परी : आवारा, शब्द
मैंने बहुत बड़े लेखकों को पढ़ा है, उन्होंने
अपने बारे में आवारा लिखा है। (व्यवधान)

डा. बापू कालदाते : आप और हम
तो कह सकते हैं . . . (व्यवधान)

श्री सीताराम के परी : इसलिए मैंने
कहा कि आवारा शब्द पर आपको एतराज
है, इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया । . .
(व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : केसरी जी,
शरत चन्द्र जी के बारे में उनको आवारा
मसीहा कहा ही जाता था, देश के सबसे
बड़े उत्ताप्नेयकार थे । . . (व्यवधान)

श्री सीताराम के परी : आप आपने
सहृदयों से कहिए। उन्होंने ही आवारा
शब्द का विश्लेषण किया है। उसके
संबंध में मैं कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

डा. बापू कालदाते : बच्चों के लिए
ठीक नहीं है। हमारे लिए ठीक है।
कहिए ।

श्री दीपेन धोष : बेसहारा कहाहा,
आवारा मत कहाहा ।

श्री सीताराम के परी : आपने पूछा
कि उनके लिए क्या क्या योजनाएँ हैं।
प्रथम योजना उनके लिए है, उनके
स्वास्थ्य को कैसे बनाया जाए, उनके चरित्र
वा निर्माण कैसे किया जाय, उनकी बोके-
शनल ट्रेनिंग दी जाए। इस तरह का कई
चीजें हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह
योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इतना ही
मेरा कहना है ।

उपसभापति : मेरें सप्लीमेंटरी ।

डा. बापू कालदाते : उपसभापति
महोदया, मेरा द्वितीय सवाल यह है बहुत
साफ है। यह कहते हैं कि कई योजनाएँ
हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या
उसकी संस्था, क्वांटम जिसकी कहाँ हैं,
क्या उसका क्वांटम सरकार के समझ प्रा-

चुका है इस तथ्य के जरिए से कि इतने प्रतिशत हो सकता है, अगर हो सकता है तो जो कुछ भी योजनाएँ आप चला रहे हैं और जो कवाटम है अगर दोनों में बहुत अंतर हो तो दोनों दिशाओं में आपको प्रयास करना चाहिए। जहां तक निवास का प्रश्न है, आप जनते हैं कि बस्वई की आवादी का 50 प्रतिशत से अधिक लोग फुटपाथ पर रहते हैं। लेकिन बच्चों के लिए निवास की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था को मैं अनिवार्य मानता हूँ। इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? आगे बाली योजना में इस समस्या के समाधान के लिए क्या कोई ठोस उपाय करने जा रहे हैं या कार्यान्वयन कर रहे हैं?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, उन बच्चों के बारे में, बेसहारा निराश्रित बच्चों के बारे में प्रश्न है। यह बच्चे आंसूमन के नीचे, वर्षा के नीचे, जाड़े में, फुटपाथ पर सोने वालों के संबंध में प्रश्न है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। आपके प्रश्न का जो अर्थ मैंने समझा है वह यह है कि उन बच्चों के बारे में जो गांदी जगहों पर रहते हैं, जिन्हें मैडिकल एड नहीं मिलती है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 90 प्रतिशत सभी तरह की सुविधाओं से विमुख रहते हैं, ऐसे बच्चों के संबंध में आपका प्रश्न है, यहां तक मैंने समझा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उनकी शिक्षा का प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि उनको शिक्षा मिले। मगर शिक्षा के लिए जब वह किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनसे यह पूछा जाता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो वह कहते हैं कि पता नहीं। कहां के रहने वाले हो तो कहते हैं कि पता नहीं। इस प्रकार से यह जहां पर स्कूल या कालेज में प्रवेश के लिए जाते हैं, वहां पर उनको अस्तीकृति मिल जाती है। ऐसी अवस्था में मैं यह सोच रहा हूँ कि इनके लिए कोई योजना बनाऊं जिससे बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध हो। जिनको मैडिकल एड नहीं मिलती है, उनके संबंध में भी मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल मैडिकल बेन का प्रबन्ध करूँ।

यह प्रश्न आपका रचनात्मक है और मैं इस दिशा में आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस दिशा में सोच रहा हूँ और मैं कुछ उदादा करना चाहता हूँ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मुझे राजकूट का यह गाना याद आ गया है, “मैं आवारा हूँ”。 फिर भी यह मैं इसमें जो “आवारा”, “स्ट्रीट चिल्ड्रेन” का अनुवाद किया गया है, यह मेरी समझ में गलत है। इसको दुरुस्त करना चाहिए... (अवधारणा)

श्री विजय कान्त शास्त्री : बेसहारा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बेसहारा हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : बेसहारा होना चाहिए। इसको आप किसी एक्सपर्ट से लिखवाकर दुरुस्त करवा दीजिए।

ये जो बच्चे हैं ये हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। जो बच्चे सड़कों के अंदर घूमते रहते हैं अक्सर जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत पुलिस उनको गलत तरीके से किसी मुकदमे में दिखा करके प्रपराधी बना देती है। मेरी समझ में जुवेनाइल एक्ट जो है वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। उसमें सुधार करने की जरूरत है। मेरा प्रश्न यह है कि जो जुवेनाइल एक्ट है इस संदर्भ में उसका क्या उसका परीक्षण करवाइएगा और यदि आवश्यकता हुई, रिपोर्ट आई तो क्या उसमें सुधार करने पर आप विचार करेंगे?

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति महोदया, मालवीय जी का प्रश्न ठीक है। सरकार भी उस पर सोच रही है कि संशोधन की आवश्यकता है।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो निराश्रित बच्चे हैं उनके बारे में उत्तर दिया कि बहुत सी उनके बारे में व्यवस्थायें की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सचमुच मैं ये बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं।

और उन्होंने पर सारा कुछ निर्भर भी है। ऐसी स्थिति में जो सर्वे कराया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो 6 बड़े बड़े महानगर हैं इनमें किस तरह से से बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं, कूड़े करकट के ढेरों में जाकर कुछ प्लास्टिक थेले और कागज इकट्ठा करते हैं, यह स्थिति बनती है इसलिए इसके बारे में जो आपने सर्वे किया है क्या उस सर्वे के आधार पर आप क्या इस नीति पर पहुंचे हैं कि वह संख्या कितनी होगी और वह संख्या अगर आ गयी है तो उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि प्रायमिकता के आधार पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप कौन कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ताकि इन बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सके और राष्ट्रीय धारा से भविष्य में जुड़कर देश के लिए कुछ निर्माण का काम कर सकें। क्योंकि यह देखा जाता है कि ये मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं और फिर आप भी जीवन उनका दूधर हो जाता है, परिवार से जो लोग अलग रहते हैं उनका जीवन और भी संकट में पड़ जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जो सदन को आश्वस्त करेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से प्रायमिकता के आधार पर कुछ ऐसे कदम उठायेंगे ताकि उनके आधार पर उनका भविष्य सुन्दर बन सके राष्ट्र के लिए ?

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति महोदय, जहाँ तक सर्वे का प्रश्न है, अमी हाल में 6 महानगरों में सर्वे हुआ है, बैगलौर, हैदराबाद, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, और दिल्ली। बार लाख के हर नगर में 20-20, 21-22 हजार लड़कों से उन्होंने उनके द्वारा जो बातें की और जो एक सैम्पूल सर्वे किया उस आधार पर 4 लाख 14 हजार तकरीबन ऐसे बच्चे हैं। जहाँ तक सारे देश के बारे में कहा, यह अनुमान पर ही कहा जा सकता है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख सम्मानित नम्बर है। जहाँ तक योजना के संबंध में कहा, यह ठीक है, कि यह प्रोग्राम बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए, भटकते हुए, बेसहारा

और निराश्रित बच्चों के लिए, जो देश का बेस बन सकते हैं, जो भविष्य है—यह सच है कि जो प्लानिंग कमीशन की तरफ से और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमें अनुदान मिलना चाहिए जो हमें योजना में प्रावधान होना चाहिए वह उसके सामने बढ़ा नगण्य है। तकरीबन 9 करोड़ का प्रावधान है। वास्तव में 9 करोड़ कुछ नहीं है। यह तो कम से कम सौ दो सौ करोड़ का प्रावधान है। फिर भी मैं प्लानिंग कमीशन के सामने, योजना आयोग के सामने, यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके, विशेष करके देश के बच्चे।

जो हमारा भविष्य है, उनके संबंध में मैं निश्चित रूप से प्रस्ताव भेजूँगा कि जो भी उन्होंने आवंटन का नियम लिया है, उससे ज्यादा इस विभाग को आवंटन करे।

SHRI SUNIL BASU RAY: Madam, I would like to know whether the Government is aware of the fact that children are occasionally subjected to different types of abuses. If so, has the Government any programme to recover these children from the streets, from the abysmal life that they lead, and rehabilitate them in the society as future citizens of India?

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति जी, जहाँ तक बच्चों के दुरुपयोग का प्रश्न है, यह दुखद अवस्था है। उसके लिए कानून उनको पकड़ता है। जहाँ तक उनके पुनर्वास का सवाल है, इसके लिए आफटर केयर होम का प्रबंध है और उसके अतिरिक्त उनके चरित्र का निर्माण, आचरण का बनाना, शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग आदि का प्रबंध है।

श्री ईश दत्त यादव : डा० बापू कालदाते जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे भावी भारत के भावी कर्णधार हो सकते हैं और हमारे कल्याण मंत्री, केसरी जी, इसके लिए चिरित भी हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं।

लेकिन मैंडम, आपके माध्यम से मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ और माननीय केसरी जी की चिता केवल महानयरों के बच्चों से ही संबंधित है और इस देश की 80 फीसदी आबादी गांव में और छोटे कस्बों में रहती है।

तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो देहातों में, छोटे कस्बों में इस तरह के बेसहारा और लावारिश बच्चे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके बारे में भी अध्ययन करवा कर, कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिसमें कि इन बच्चों का भी भविष्य सुधर सके और वह देश के अच्छे और सम्पन्न नागरिक बन सके।

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति जी, जहां तक छोटे कस्बों का प्रश्न है इस दिशा में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ... (व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव : गांव के भी ...

श्री सीताराम केसरी : गांव की बात, अच्छा। जहां तक गांव का प्रश्न है, मझे, जहां तक गांव की जानकारी है और आप भी जानकारी रखते हैं, वहां इस तरह के बच्चे न तो सम्पन्न परिवार के गलत रास्ते पर जाते हैं और न विपन्न परिवार के गलत रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि वहां सम्प्रता नहीं है। इस सारी जीवानी की जड़ है इडीस्ट्रियल एरा, आधुनिक युग। दुखद बात तो यह है कि इस की बजह से ड्रग है, इसकी बजह से टॉरोरिस्ट है, इसकी बजह से सारा दुर्गम बच्चों में है।

इसलिए जो गांधी जी ने बताया था, उस रास्ते से हम भ्रमित हो गए हैं। अगर उस रास्ते पर चले होते, तो इनके चरित्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता, नीचे से चरित्र निर्माण हो कर के आता। (व्यवधान)

श्री बीरेन जे. शाह : ऊपर से जा रहा है। ..(व्यवधान) तो नीचे से नहीं हो सकता। ..(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : सुनिए तो यह सारी चीज आप नहीं समझिएगा। आपके महाजन समझेंगे, आप नहीं समझेंगे इस चीज को—जो जमीन का कार्यकर्ता है, वह समझता है, यह चरित्रहीनता बच्चों में, इस तरह के दण्ड का कारण क्या है। यह क्यों हजारोंलाखों की संख्या में प्लायनवादी हो गए, क्यों ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं, क्यों इस तरह देश की जो बच्चों के द्वारा नीचे है, वह बर्बाद हो रही है।

इसके लिए मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक गांवों की बात है, वहां यह प्रश्न नहीं है, जो कस्बों की बात कही है, वहां यह प्रश्न है।

श्री भूबनेश चतुर्वेदी : उपसभापति जी, बात पूर्व जन्म की है, 1970, 1971, तथा 1972 में जब हमने अपनी नीतियों का पुनर्विचार करना प्रारंभ नहीं किया था और अपनी नीतियों के हम खुद आलोचक नहीं बने थे, तब बात चली भी, कल्पना, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में कि एक सोशलिस्ट चार्टर फार चिल्ड्रन बनाया जाए।

और बात कुछ आई गई हो गई। मैं मंत्री महोदय से पूछता चाहूँगा कि क्या सोशलिस्ट चार्टर फार चिल्ड्रन की कल्पना अभी आपके मंत्रालय में या आपकी सरकार में है? अगर है तो, उसको आप क्या रूप देना चाहेंगे अथवा वह नई नीतियों के आधार पर इर्नेवेंट बन चुकी है?

श्री सीताराम केसरी : सोशलिस्ट चार्टर के आधार कहिए, समाजवादी दी चार्टर के आधार पर कहिए या गांधीवादी चार्टर के आधार कहिए, बच्चों के जीवन को, उनके आचरण को और चरित्र को ... (व्यवधान)

श्री भूबनेश चतुर्वेदी : सोशलिस्ट चार्टर फार चिल्ड्रन को बात है?

श्री सीताराम केसरी : वही मैं कह रहा हूँ, जहां पर किशोर बच्चों के चरित्र निर्माण का प्रश्न है उनके लिए कई तरह का मैंने बताया कि आज्ञवेशन होम है, स्पेशल होम है और आफ्टर केयर होम है, उसी के अंतर्गत योजना है। मगर

आपका प्रश्न जो आपने मझे याद दिलाया उस दिशा में भी सोच की आवश्यकता है और यह सोची जाएगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next Question No. 442.

*(The question (Shri Misa R. Ganesan was absent. For answer, vide col.... infra).

*(The question (Dr. Sanjaya Sinh) was absent. For answer, vide col.... infra).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 444. Shri Maheshwar Singh.

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों का चयन

* 444. श्री महेश्वर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेल-कदम संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न राज्यों में कुछ विद्यालयों का चयन करता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय इस प्रयोजनार्थ चुने गये विद्यालयों को राज्य-वार संभाया कितनी है और ऐसी सुविधाएं

कितने विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण का व्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारता बनर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 56 स्कूलों को अपनाया गया है। इस योजना में राज्यवार छात्रों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ग) यह योजना 1985 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य 8-12 वर्ष के आयु समूह में स्कूली छात्रों में प्रतिभा की खोज करना था। इस योजना से एडलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, बालीबाल तथा कुश्ती खेल-विधाएं शामिल हैं योजना में छोटी आयु में खेल उत्कृष्टता के साथ छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की परिकल्पना है। इसका सम्पूर्ण वर्च भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बहुत किया जाता है।

विवरण

अंगीकृत विद्यालयों में छव्वों की संख्या (राज्य-वार) - 31.3.92 तक की स्थिति

राज्य का नाम	विद्यालय का नाम	छव्वों की संख्या	
लड़के	लड़कियां		
1	2	3	4
भारत प्रदेश	1. वैसली बाल उच्च विद्यालय तथा महाविद्यालय, सिकंदराबाद 2. वी. पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा 3. लेयोसा उच्च विद्यालय, बेनकोण्डा	17 25 09	— 14 03